



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 947]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 17, 2010/वैशाख 27, 1932

No. 947]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 17, 2010/VAISAKHA 27, 1932

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मई, 2010

का.आ. 1124(अ).—दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति सुश्री हिमा कोहली की अध्यक्षता में गठित अधिकरण, जिसको विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 4(1) के अंतर्गत न्यायनिर्णय करने संबंधी मामला भेजा गया था कि मणिपुर के मैतई उग्रवादी संगठनों अर्थात् पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पी एल ए), रिवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट (आर पी एफ), यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यू एन एल एफ), पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपाक (पी आर ई पी ए के), कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी (के सी पी), कांगली याओल कानबा लुप (के वाई के एल) और मणिपुर पीपल्स लिबरेशन फ्रंट (एम पी एल एफ) को विधिविरुद्ध संगम घोषित किए जाने के पर्याप्त कारण हैं या नहीं, के आदेश को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 4(4) के अनुसार आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री हिमा कोहली, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में
विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण की रिपोर्ट

मणिपुर के निम्नलिखित मैतई उग्रवादी संगठनों अर्थात्,

1. पीपल्स लिबरेशन आर्मी जिसे सामान्यतः पी एल ए के नाम से जाना जाता है;
2. रिवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट (आर पी एफ);
3. यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यू एन एल एफ);

4. पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपाक (पी आर ई पी ए के) और इसके सशस्त्र विंग जिसे "रेड आर्मी" भी कहा जाता है;
5. कांगलीपाक कम्यूनिस्ट पार्टी (के सी पी) और इसके सशस्त्र विंग जिसे "रेड आर्मी" भी कहा जाता है;
6. कांगली याओल कानबा लुप (के वाई के एल); और
7. मणिपुर पीपल्स लिबरेशन फ्रंट (एम पी एल एफ)

को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत "विधिविरुद्ध संगम" घोषित किए जाने के मामले में:

1. भारत सरकार ने विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके बाद "अधिनियम" कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मणिपुर के मैतेई उग्रवादी संगठनों, अर्थात् (1) पीपल्स लिबरेशन आर्मी जिसे पी एल ए के नाम से जाना जाता है; (2) रिवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट (आर पी एफ); (3) यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यू एन एल एफ); (4) पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपाक (पी आर ई पी ए के) और इसके सशस्त्र विंग "रेड आर्मी"; (5) कांगलीपाक कम्यूनिस्ट पार्टी (के सी पी) और इसके सशस्त्र विंग जिसे "रेड आर्मी" भी कहा जाता है; (6) कांगली याओल कानबा लुप (के वाई के एल); और (7) मणिपुर पीपल्स लिबरेशन फ्रंट (एम पी एल एफ) के साथ-साथ इनके सभी घटकों, शाखाओं और अग्रणी संगठनों (जिन्हें इसमें इसके बाद "मैतेई उग्रवादी संगठन" कहा गया है) को अपनी दिनांक 13.11.2009 की अधिसूचना के तहत विधिविरुद्ध संगम घोषित किया था।

2. उक्त अधिसूचना में यह उल्लेख किया गया है कि केन्द्र सरकार का यह मत है कि यदि मैतेई उग्रवादी संगठनों की विधिविरुद्ध गतिविधियों पर तत्काल अंकुश तथा नियंत्रण नहीं लगाया गया तो उन्हें निम्नलिखित के अवसर प्राप्त हो जाएंगे:-

- (i) अपनी अलगाववादी, विध्वंसकारी, आतंकवादी एवं हिंसक गतिविधियों को तेज करने के लिए अपने काइरों को एक जुट करना;
- (ii) भारत की संप्रभुता तथा अखंडता के लिए हानिकर ताकतों के साथ मिलकर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का विस्तार करना;
- (iii) आम नागरिकों की हत्याओं में वृद्धि करना तथा पुलिस और सुरक्षा बल कार्मिकों को निशाना बनाना;

- (iv) अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार से अधिक मात्रा में अवैध शस्त्र एवं गोलाबारूद प्राप्त करना तथा जुटाना;
- (V) अपनी विधिविरुद्ध गतिविधियों के लिए जनता से बड़ी मात्रा में जबरन धन ऐंठना तथा निधियां इकट्ठी करना।

3. आगे यह भी उल्लेख किया गया है कि इन उग्रवादी संगठनों ने खुलेआम यह घोषणा की है कि उनका उद्देश्य मणिपुर राज्य को भारत से अलग करके एक स्वतंत्र मणिपुर राष्ट्र का गठन करना है और वे ऊपर उल्लिखित अपने उद्देश्यों को हासिल करने के लिए सशस्त्र साधनों का इस्तेमाल तथा प्रयोग कर रहे हैं। ये सुरक्षा बलों, पुलिस, सरकारी कर्मचारियों और मणिपुर की आम जनता पर लगातार हमले कर रहे हैं। ये अपने संगठनों के लिए निधियां इकट्ठा करने के लिए डराने, धमकाने, जबरन धन ऐंठने तथा आम जनता से लूटपाट करने के कृत्यों में शामिल रहे हैं। ये अपने अलगाववादी उद्देश्य को हासिल करने के प्रयोजन से जनमत को प्रभावित करने तथा शस्त्रों एवं प्रशिक्षण के रूप में उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए विदेशों में अपने संपर्क स्थापित करने के प्रयास भी करते रहे हैं और ये सुरक्षित शरण-स्थली, प्रशिक्षण तथा हथियार गोलाबारूद के गुप्त तरीके से प्रापण के प्रयोजन से पड़ोसी देशों में शिविर बनाए हुए हैं। यह भी उल्लेख किया जाता है कि मैतेई उग्रवादी संगठनों की गतिविधियां भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकार हैं। उपर्युक्त कारणों और आधार पर केन्द्र सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची कि उक्त संगठन विधिविरुद्ध संगम है।

4. भारत सरकार ने, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के तहत मैतेई उग्रवादी संगठनों को दिनांक 13.11.2009 से दो वर्ष की अवधि के लिए "विधिविरुद्ध संगम" घोषित करते समय निम्नलिखित आधारों पर भी विचार किया है:

- i) मणिपुर को भारत से अलग करने की नीति को अपनाना जारी रखना;
- ii) भारत की एकता और संप्रभुता के लिए खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों में संलिप्तता जारी रखना;
- iii) अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए साधनों के तौर पर सशस्त्र कार्रवाई के माध्यम से हिंसा और भय बनाए रखना;

- iv) व्यावसायियों, व्यापारियों और यहां तक कि सरकारी कर्मचारियों सहित जनता से अत्यधिक अवैध कर-वसूली और जबरन धन-वसूली करना;
- v) अन्य पूर्वोत्तर विद्रोही गुटों के साथ संपर्क रखना और उन्हें समर्थन देना और पड़ोसी देशों के साथ संपर्क रखना;
- vi) गुप्त माध्यमों द्वारा या पुलिस और सुरक्षा बलों से छीनकर बड़ी संख्या में अत्याधुनिक हथियारों और गोलाबारूद का प्रापण।

5. केन्द्र सरकार ने दिनांक 13 नवम्बर, 2009 की अपनी अधिसूचना सं. 2883 (अ) के माध्यम से मैतेई उग्रवादी संगठनों को विधिविरुद्ध संगम के रूप में घोषित किया था। केन्द्र सरकार ने, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 11 दिसम्बर, 2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 3180 (अ) के तहत यह न्याय निर्णय करने के लिए इस अधिकरण का गठन किया कि क्या उक्त मैतेई उग्रवादी संगठनों को विधिविरुद्ध संगम घोषित किए जाने के पर्याप्त कारण हैं अथवा नहीं जैसा कि इस अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित है।

6. उपर्युक्त संदर्भ भेजे जाने के पश्चात् अधिकरण ने इस अधिनियम की धारा 4 (2) के उपबंध के अनुसरण में दिनांक 23 दिसम्बर, 2009 के आदेश के तहत उक्त मैतेई उग्रवादी संगठनों को इस संबंध में एक कारण बताओ नोटिस जारी किया कि वे इस नोटिस की तामीली की तारीख से 30 दिन के भीतर यह बताएं कि क्यों न उक्त संगठनों को विधिविरुद्ध संगम घोषित कर दिया जाए। अधिकरण ने यह भी निदेश दिया कि नोटिस की तामीली निम्न तरीकों से की जाए:

- (i) उपर्युक्त संगमों के कार्यालयों, यदि कोई हों, के किसी मुख्य भाग पर नोटिस की प्रति चिपकाकर;
- (ii) मणिपुर राज्य, जहां ऊपर उल्लिखित संगठनों की गतिविधियां सामान्यतया जारी रहती हैं, के एक राष्ट्रीय अंग्रेजी समाचार पत्र और एक स्थानीय भाषा के समाचार पत्र, जो मणिपुर राज्य में परिचालित हो रहे हों, में प्रकाशन द्वारा;
- (iii) जहां कहीं संभव हो, संगमों के प्रमुख पदाधिकारियों, यदि कोई हों, को नोटिस की प्रति की तामीली द्वारा;

- (iv) जिला या तहसील मुख्यालय, जहां संगमों के प्रधान कार्यालय स्थित हैं, में जिला मजिस्ट्रेट या तहसीलदार के कार्यालय, जैसा भी मामला हो, के सूचना पट्ट पर नोटिस चिपकाकर;
- (v) ऐसे क्षेत्र में जहां संगमों की गतिविधियां सामान्यतया चलाई जाती हों, ढोल बजाकर या लाउडस्पीकरों के माध्यम से नोटिस की विषय-वस्तु की उदघोषणा द्वारा; और
- (vi) आकाशवाणी के स्थानीय या निकटतम प्रसारण केन्द्र से रेडियो पर प्रसारण द्वारा।

7. अधिकरण ने अपने पंजीयक को भी नोटिसों की तामीली का पर्यवेक्षण करने का निदेश दिया। नोटिसों की तामीली के संबंध में पंजीयक की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई थी। भारत संघ द्वारा तामीली संबंधी शपथपत्र दाखिल किया गया।

8. रिकार्डों में उपलब्ध सामग्री के अतिरिक्त अधिकरण के पंजीयक की रिपोर्ट से इस बारे में अधिकरण संतुष्ट हो गया था कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) नियम, 1968 के नियम 6 में यथानिर्धारित निर्देशों के अनुसार पूर्वोक्त संगठनों/संगमों को विधिवत रूप से नोटिसों की तामीली कर दी गई है।

9. दिनांक 23.12.2009, 10.2.2010, 23.2.2010, 4.3.2010, 22.3.2010, 1.4.2010, और 8.4.2010 के आदेशों द्वारा मैतेई उग्रवादी संगठनों को अपने उत्तर/शपथ-पत्र दाखिल करने और सुनवाई की तारीखों पर अधिकरण के समक्ष स्वयं को पेश किए जाने के लिए दिए गए तमाम अवसरों के बावजूद, कोई भी संगठन अधिकरण के समक्ष पेश नहीं हुआ है और न ही नोटिस के प्रत्युत्तर में कोई कारण दर्शाया गया।

10. दिनांक 22.3.2010 को शिलांग में हुई अधिकरण की सुनवाई में अभियोजन गवाह-1, श्री देवेश देवाल, संयुक्त सचिव (गृह), मणिपुर सरकार के आंशिक साक्ष्य को रिकार्ड किया गया और उनके बयान को सुनवाई की अगली तारीख तक आस्थगित कर दिया गया ताकि वे कुछ और दस्तावेज प्रस्तुत कर सकें। मणिपुर सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों, जिन्होंने साक्ष्य के रूप में अपने-अपने शपथ-पत्र दायर किए थे, को शपथ दिलाकर पूछताछ की गई और उनके बयान रिकार्ड किए गए:

अभियोजन गवाह-2 श्री सारंगथेम इबोम्चा सिंह, उप पुलिस अधीक्षक (सी डी ओ) इम्फाल,

अभियोजन गवाह-3 श्री मो0 हुस्ने जमान, एस डी पी ओ, मोईरंग, मणिपुर;

अभियोजन गवाह-4 श्री के. मेघचन्द्रा सिंह, सी डी पी ओ, लामलई, इम्फाल पूर्व जिला, मणिपुर;

अभियोजन गवाह-5 श्री टी. लालबोई हेओकिप, एस डी पी ओ, थुबाल, मणिपुर।

11. दिनांक 1.4.2010 को दिल्ली में हुई अधिकरण की सुनवाई में भारत सरकार के निम्नलिखित अधिकारी, जिन्होंने साक्ष्य के रूप में अपना शपथ-पत्र प्रस्तुत किया था, को शपथ दिलाकर पूछताछ की गई और उनके बयान को रिकार्ड किया गया:

अभियोजन गवाह-6 श्री आर.आर. झा, निदेशक (पूर्वोत्तर), गृह मंत्रालय, भारत सरकार

उसी दिन, अभियोजन गवाह-1, श्री देवेश देवाल, संयुक्त सचिव (गृह), मणिपुर सरकार के शेष साक्ष्य को रिकार्ड किया गया।

12. दिनांक 8.4.2010 को गुवाहाटी में अधिकरण की हुई सुनवाई में मणिपुर सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों, जिन्होंने साक्ष्य के रूप में अपने-अपने शपथ-पत्र दायर किए थे, को शपथ दिलाकर पूछताछ की गई और उनके बयान रिकार्ड किए गए:

अभियोजन गवाह-7 श्री टीएच. विक्रमजीत सिंह, एस डी पी ओ, सिंगजामई, मणिपुर;

अभियोजन गवाह-8 श्री लाइशरम बीरबाबू सिंह, एस डी पी ओ, पोरामपट, इम्फाल (पूर्व) मणिपुर;

अभियोजन गवाह-9 श्री एन. मधुनीमई सिंह, एस डी पी ओ, इम्फाल, (पश्चिम) मणिपुर;

अभियोजन गवाह-10 श्री एम. रामेश्वर सिंह, एस डी पी ओ, मोरेह, मणिपुर।

13. उनकी मुख्य जांच के दौरान, ऊपर उल्लिखित सभी गवाहों ने अपने संबंधित शपथ-पत्रों पर अपने-अपने हस्ताक्षरों को स्वीकार किया और इनमें उल्लिखित सभी प्रदर्शों के साथ अपने शपथ-पत्र प्रस्तुत किए और उनके साक्ष्य के एक हिस्से के रूप में इनके साथ संलग्न किए।

14. यथापूर्वोक्त दिए गए अवसरों के बावजूद पूर्वोक्त मैतेई संगठनों के लिए कोई भी गवाहों की प्रतिपरीक्षा के लिए अधिकरण के समक्ष पेश नहीं हुआ। इसलिए गवाहों को छोड़ दिया गया। चूंकि इस अधिकरण अथवा इसके पंजीयक किसी के द्वारा पूर्वोक्त उग्रवादी संगठनों से कोई प्रतिवेदन, संदेश अथवा कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं किया गया था, इसलिए साक्ष्य को समाप्त कर दिया गया। चूंकि इस अधिकरण अथवा इसके पंजीयक में से किसी के द्वारा पूर्वोक्त उग्रवादी

संगठनों से कोई प्रतिवेदन, संदेश अथवा कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं किया गया था, इसलिए साक्ष्य को समाप्त कर दिया गया।

15. भारत संघ की ओर से श्री ए.एस. चण्डिओक, ए.एस.जी. तथा सहायक श्री बलदेव मलिक, अधिवक्ता द्वारा जिरह की गई। विद्वान अधिवक्ताओं ने अनुरोध किया कि केन्द्र सरकार द्वारा विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3 (1) के तहत जारी की गई दिनांक 13.11.2009 की अधिसूचना संख्या 2883 (अ), जिसके द्वारा पूर्वोक्त मैतेई अतिवादी संगठनों को विधिविरुद्ध संगम घोषित किया गया था, की पुष्टि की जाए।

16. अधिकरण ने रिकार्ड में रखे गए दस्तावेजी साक्ष्य और भारत संघ तथा मणिपुर राज्य द्वारा प्रस्तुत किए गए शपथपत्रों एवं मौखिक साक्ष्य का अध्ययन किया है।

17. पी डब्ल्यू-1 श्री देवेश देवल, संयुक्त सचिव (गृह), मणिपुर सरकार ने साक्ष्य के रूप में अपने शपथपत्र में कहा है कि मणिपुर में विद्रोह की समस्या पिछले कई वर्षों से महामारी की तरह फैल रही है और यह मैतेई अतिवादी संगठनों, नामतः, पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पी एल ए), जो रिवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट (आर पी एफ) के रूप में ज्ञात संगठन की एक सशस्त्र विंग है; दी पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांग्लेईपाक (पी आर इ पी ए के); दी यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यू एन एल एफ); दी कांग्लेई याओल कांबा लुप (के वाई के एल); दी कांग्लेईपाक कम्युनिस्ट पार्टी (के सी पी); और दी मणिपुर पीपल्स लिबरेशन फ्रंट (एम पी एल एफ) की देन है। उनके द्वारा यह कहा गया कि मणिपुर राज्य सरकार को इन मैतेई अतिवादी संगठनों द्वारा मणिपुर राज्य में पैदा की गई विद्रोह की समस्या से निपटना पड़ता है तथा कि इन संगठनों का मुख्य उद्देश्य, जैसाकि उनके द्वारा दृढ़तापूर्वक कहा गया था, मणिपुर को भारत संघ से अलग करना तथा इसे एक स्वतंत्र प्रभुसत्ता सम्पन्न देश बनाना है। दूसरे शब्दों में, भारत के प्रभुत्व से मणिपुर राज्य को स्वतंत्र कराना उक्त संगठनों का उद्देश्य बताया गया था। उक्त गवाह द्वारा आगे यह वक्तव्य दिया गया कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उक्त मैतेई उग्रवादी संगठन विभिन्न विधिविरुद्ध गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं जैसे डराना-धमकाना, आम जनता से धन की जबरन वसूली करना, भोले-भाले लोगों, सरकारी कर्मचारियों, पुलिस कर्मियों तथा सुरक्षा बलों के कर्मियों की हत्या जैसे कृत्यों द्वारा लोगों में दहशत पैदा करना, फिरोती के प्रयोजनार्थ बड़ी राशि

की मांग आदि करके उच्च रैंक के सरकारी अधिकारियों, व्यापारियों तथा धनी परिवारों के सदस्यों का अपहरण और अगवा करना। यह भी कहा गया कि अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए इन संगठनों को विदेशों से विशेषकर पड़ोसी देशों से, शरण और आश्रय, प्रशिक्षण, शस्त्रों और गोलाबारूद के प्रापण के रूप में सहायता मिलती रही है।

18. रिवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट (आर पी एफ) और पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पी एल ए) के संबंध में, यह बताया गया है कि म्यांमार तथा बंगलादेश में इन संगठनों के प्रशिक्षण केन्द्र हैं। यह भी बताया गया है कि आर पी एफ एक राजनीतिक इकाई है और पी एल ए एक सशस्त्र इकाई है। ये दोनों इकाईयां एक ही संगठन के अंग हैं। यह बताया गया है कि इनकी कार्यप्रणाली दुपहिया वाहनों पर घूमना या छोटे हथियारों या स्वचालित हथियारों की सहायता से शहर या उसके बाहरी इलाकों से चार पहिया वाहनों का अपहरण कर लेना है। यह भी बताया गया है कि इन इकाईयों के सदस्य लड़ाकू वेशभूषा में हथियारों के साथ खुलेआम समूहों में घूमते हैं और पुलिस चौकियों, सीमा चौकियों पर हमला करते हैं तथा सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला करते हैं और सरकारी विभागों, कर्मचारियों, व्यापारियों आदि से धन वसूलते हैं। इन इकाईयों के एन एस सी एन (के), यू एन एल एफ, पी आर ई पी ए के, टी डी पी एफ, उल्फा, के सी पी, यू पी पी के, इत्यादि जैसे अन्य इसी प्रकार के संगठनों के साथ घनिष्ठ संबंध बताए जाते हैं। यह एम पी एल एफ (मणिपुर पीपल्स लिबरेशन फ्रंट) का भी एक सदस्य है जिसकी स्थापना 01.03.1999 को पी आर ई पी ए के, आर पी एफ और यू एन एल एफ के अध्यक्षों के द्वारा एक संयुक्त घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करके की गई। पी डब्ल्यू-1 द्वारा आगे यह भी बताया गया है कि इन दो इकाईयों के पास ए के/47, ए के/56, ए के/86, एम-16, एम-18, एम-21, एम-22, एम/20, एम/23, लाइट मशीनगन, एल एम जी और रॉकेट लांचर्स जैसे करीब 550 से ज्यादा अत्याधुनिक हथियार हैं तथा इसके साथ ही करीब 2000 अन्य हथियार भी हैं।

19. यूनाईटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यू एन एल एफ), पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांग्लेइपाक (पी आर इ पी ए के), कांग्लेई याओल कांबा लुप (के वाई के एल) (कांग्लेइपाक कम्युनिस्ट पार्टी (के सी पी), और मणिपुर पीपल्स लिबरेशन फ्रंट (एम पी एल एफ) के संबंध में उक्त पी डब्ल्यू-1 द्वारा इसी प्रकार के बयान दिए गए हैं।

20. पी डब्ल्यू-1 के शपथपत्र के साथ, मैतेई उग्रवादी संगठनों के विरुद्ध 13.11.2007 से 15.6.2009 की अवधि के लिए दर्ज कराई गई प्राथमिकियों की सत्यापित प्रतियां जब्ती जापनों के साथ फाईल की गई हैं और इन्हें प्रदर्श पी डब्ल्यू ¼ से 1/9 के रूप में चिह्नित किया गया है। प्रदर्श पी डब्ल्यू 1/10 (कोली) में विभिन्न प्रतिबंधित संगठनों द्वारा किए गए अपराधों के संक्षिप्त विवरण, साहित्य, पर्चे आदि जैसे जब्त किए गए दस्तावेज, अखबारों की कतरनें और इन संगठनों को तत्काल विधिविरुद्ध संगम घोषित किए जाने के औचित्य का विवरण शामिल है। प्रदर्श पी डब्ल्यू-1/11 रिपोर्टों में प्रयुक्त पुलिस थानों से संबंधित संक्षेपणों की सूची है। इन संगठनों की गतिविधियों के बारे में पुलिस अधीक्षक द्वारा तैयार की गई विशेष रिपोर्टों की अनुप्रमाणित प्रतियां संयुक्त रूप से प्रदर्श पी डब्ल्यू-1/12 के रूप में चिह्नित की गई हैं। प्रदर्श पी डब्ल्यू-1/13 इन संगठनों द्वारा समय-समय पर स्थानीय समाचार पत्रों में जारी की गई प्रेस रिलीज़ की प्रतियां हैं।

21. पी डब्ल्यू-1 द्वारा बयान दिया गया है कि ये प्रतिबंधित संगठन नेमी रूप से राष्ट्रीय समारोहों अर्थात् स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, का प्रतिवर्ष बहिष्कार करते हैं। ये प्रेस रिलीज़ जारी करते हैं जिनमें लोगों से इन समारोहों में भाग न लेने की अपील की जाती है और इन संगठनों के डर से इन समारोहों में लोगों की उपस्थिति बहुत कम होती है। उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने उक्त संगठनों की विधिविरुद्ध संगम के रूप में घोषणा को जारी रखने की सिफारिश की है। अभिसाक्षी ने यह भी बताया है कि मणिपुर सरकार और भारत सरकार द्वारा ईमानदारी से किए गए प्रयासों के बावजूद ये अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सफल नहीं हुई हैं और पिछले कुछ समय से इन संगठनों की गतिविधियों में काफी वृद्धि हुई है और अतः इन संगठनों को विधिविरुद्ध घोषित किए जाने की आवश्यकता आज भी बनी हुई है ताकि मणिपुर सरकार कानून और व्यवस्था की समस्याओं से प्रभावी तरीके से निपट सके।

22. मणिपुर पुलिस सेवा के 8 अधिकारियों के बयान दर्ज किए गए थे। इन गवाहों अर्थात् पी डब्ल्यू-2 से 5 तक और पी डब्ल्यू-7 से 10 तक ने साक्ष्य के रूप में अपने-अपने शपथपत्र प्रस्तुत किए और विभिन्न प्राथमिकियों के संबंध में उनके द्वारा की गई जांचों के बारे में साक्ष्य दिया। इन गवाहों ने कहा कि उक्त संगठनों पर लगाया गया प्रतिबंध जारी रहना चाहिए।

23. पी. डब्ल्यू-6, श्री आर.आर. झा, निदेशक, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने साक्ष्य के रूप में दिनांक 9.2.2010 का अपना शपथपत्र प्रस्तुत किया और कहा है कि मणिपुर में उग्रवादी गतिविधियां मुख्य रूप से मैतेई उग्रवादियों द्वारा चलाई जा रही हैं। मणिपुर में वर्तमान सुरक्षा स्थिति को देखते हुए इम्फाल नगरपालिका क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण मणिपुर राज्य को मणिपुर के राज्यपाल द्वारा सशस्त्र बल (विशेष शक्ति) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत समय-समय पर विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि उक्त संगठनों का घोषित उद्देश्य मणिपुर राज्य को भारत से अलग करके एक स्वतंत्र प्रभुसत्ता सम्पन्न मणिपुर राज्य की स्थापना करना है और ये उग्रवादी गुट अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सशस्त्र साधनों का प्रयोग कर रहे हैं।

24. उन्होंने आगे कहा कि मणिपुर राज्य में कमजोर कानून और व्यवस्था की स्थिति हमेशा एक चिंता का विषय बनी रहती है। मैतेई उग्रवादी संगठनों का मुख्य निशाना सुरक्षा बल रहते हैं। इन उग्रवादी संगठनों द्वारा की गई हिंसक घटनाओं का ब्यौरा, जो उनके शपथपत्र के पैरा-4 में दिया गया है, उसे नीचे दर्शाया गया है :-

वर्ष	कुल घटनाएं	मैतेई समूहों द्वारा की गई घटनाएं	मैतेई समूहों द्वारा मारे गए कुल सिविलियन/सुरक्षा बल कर्मिक	मैतेई समूहों द्वारा मारे गए सुरक्षा बल कर्मिक
2007	584	396	122	37
2008	740	492	94	10
2009 (31 दिसम्बर तक)	659	485	77	17

25. उन्होंने आगे बयान में कहा कि ये उग्रवादी संगठन राष्ट्रीय पर्वों के आयोजन का बहिष्कार करते रहे हैं। हिंसक वारदातों के अलावा ये आम जनता से जबरन धन वसूली में तथा विकास के लिए नियत निधियों को बलपूर्वक हड़पने की गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। मैतेई उग्रवादी संगठनों ने राज्य के गैर-मणिपुरी निवासियों के विरुद्ध अपना अभियान तेज कर दिया है। वर्ष 2008 के दौरान पूरे वर्ष में की गई 21 गैर-मणिपुरी हत्याओं की तुलना में मैतेई

उग्रवादी संगठन अब तक राज्य में 22 गैर-मणिपुरी लोगों की हत्या में शामिल थे। ये उग्रवादी संगठन राज्य में विभिन्न समुदायों के बीच मतभेद एवं विद्वेष पैदा करने के उद्देश्य से स्थानीय मैतेई संगठनों को मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा तथा सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 को समाप्त करने सहित विभिन्न मुद्दों पर आंदोलन चलाने के लिए अपना समर्थन देते रहे हैं। 02.01.2009 से 29.05.2009 तक की अवधि में इन संगठनों द्वारा की गई घटनाओं का सार प्रदर्श पी डब्ल्यू 6/पृष्ठ 2 के रूप में दर्शाया गया है।

26. उन्होंने बयान दिया कि मैतेई संगठन पूर्वोत्तर में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असोम (उल्फा), ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (ए टी टी एफ) तथा नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एन एल एफ टी) जैसे अन्य उग्रवादी संगठनों के साथ निकट संबंध रखते हैं जिन्हें विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अंतर्गत विधिविरुद्ध संगम घोषित किया गया है। इनके नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (एन एस सी एन (आई/एम)) तथा नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (एन एस सी एन (के)) के साथ भी निकट संबंध हैं। मैतेई उग्रवादी संगठन, हथियारों के प्रापण में सहायता लेने तथा अपने अलगाववादी उद्देश्यों की प्राप्ति के प्रयोजन से उनके काडरों को प्रशिक्षित करने के लिए अन्य उग्रवादी संगठनों से निकट संबंध बनाए हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि पी एल ए/आर पी एफ, यू एन एल एफ, पी आर ई पी ए के, के सी पी, के वाई के एल तथा एम पी एल एफ के बंगलादेश तथा म्यांमार में शिविर हैं। ये उग्रवादी संगठन मणिपुर में अपनी भारत विरोधी गतिविधियां चलाने के लिए इन देशों से हथियार एवं गोलाबारूद भी प्राप्त करते रहे हैं।

27. पी. डब्ल्यू-6 ने आगे यह बयान दिया कि इन संगठनों को अधिसूचना की तारीख से विधिविरुद्ध संगम घोषित किया गया है क्योंकि केन्द्र सरकार द्वारा यह महसूस किया गया है कि पूर्व अधिसूचना की समाप्ति की तारीख तथा वर्तमान अधिसूचना की तारीख के बीच कोई अन्तराल नहीं होना चाहिए जिससे कि पुलिस और सुरक्षा बल गिरफ्तारियां तथा इन संगठनों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई लगातार कर सकें और ये संगठन राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में संलिप्त न हों। भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 13.11.2009 की उक्त अधिसूचना प्रदर्श पी डब्ल्यू 6/पी 3 के रूप में चिह्नित की गई है।

28. अधिकरण ने, मणिपुर राज्य तथा केन्द्र सरकार द्वारा अलग-अलग सीलबंद लिफाफे में सौंपे गए गुप्त दस्तावेजों की भी जांच की है।

29. अधिकरण ने, भारत संघ तथा मणिपुर सरकार द्वारा रिकार्ड के लिए रखे गए दस्तावेजी साक्ष्य और प्रस्तुत किए गए शपथपत्रों और मौखिक साक्ष्य की अच्छी तरह से जांच-पड़ताल की है।

30. केन्द्र सरकार तथा मणिपुर सरकार की ओर से दिए गए साक्ष्य परस्पर विरोधी नहीं हैं। उनके खंडन के लिए रिकार्ड में कुछ भी नहीं है। विभिन्न गवाहों द्वारा दिए गए बयानों और मौखिक-साक्ष्यों और शपथपत्रों के समर्थन में साक्ष्य के तौर पर दायर दस्तावेजी साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

31. सभी साक्ष्यों और रिकार्ड की पूरी सामग्री पर विचार करने के पश्चात्, अधिकरण का यह मत है कि मैतेई उग्रवाई संगठनों को विधिविरुद्ध घोषित करने का पर्याप्त कारण था। परिणामस्वरूप यह अधिकरण, केन्द्र सरकार द्वारा विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3 (1) के अंतर्गत जारी की गई दिनांक 13.11.2009 की अधिसूचना सं. 2883 (अ) में की गई घोषणा की पुष्टि करता है।

[फा. सं. 11011/34/2009-एन ई-III]

नवीन वर्मा, संयुक्त सचिव

04.05.2010

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th May, 2010

S.O. 1124(E).—In terms of Section 4 (4) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the order of the Tribunal presided over by Hon'ble Ms. Justice Hima Kohli, Judge, Delhi High Court, to whom a reference was made under Section 4(1) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 for adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the Meitei Extremist Organisations of Manipur, viz., the People's Liberation Army (PLA), the Revolutionary Peoples' Front (RPF), the United National Liberation Front (UNLF), the Peoples' Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK), the Kangleipak Communist Party (KCP), the Kanglei Yaol Kanba Lup (KYKL) and the Manipur People's Liberation Front (MPLF), as unlawful is published for general information :

**REPORT OF THE UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) TRIBUNAL PRESIDED
OVER BY HON'BLE MS. JUSTICE HIMA KOHLI, JUDGE OF DELHI HIGH COURT**

In the Matter of :

Declaration of the Meitei Extremist Organisations of Manipur, namely,

1. The Peoples' Liberation Army generally known as PLA;
2. The Revolutionary Peoples' Front (RPF)
3. The United National Liberation Front (UNLF)
4. The Peoples' Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK) and its armed wing, also called the "Red Army";
5. The Kangleipak Communist Party (KCP) and its armed wing also called the "Red Army";
6. The Kanglei Yaol Kanba Lup (KYKL) and
7. The Manipur Peoples' Liberation Front (MPLF)

"To be Unlawful Associations" under Sub-section (1) of Section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967).

1. The Government of India in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), (hereinafter referred to as "the Act") declared the Meitei Extremist Organisations of Manipur, namely, (1) The Peoples' Liberation Army known as PLA; (2) The Revolutionary Peoples' Front (RPF); (3) The United National Liberation Front (UNLF); (4) The Peoples' Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK) and its armed wing, the "Red Army"; (5) The Kangleipak Communist Party (KCP)

and its armed wing, also called the "Red Army" ; (6) The Kanglei Yaol Kanba Lup (KYKL); and (7) The Manipur Peoples' Liberation Front (MPLF), along with all their factions, wings and front organisations (hereinafter referred to as "the Meitei Extremist Organizations") as Unlawful Associations vide its notification dated 13.11.2009.

2. It is stated in the said notification that the Central Government is of the opinion that if the Unlawful Activities of the Meitei Extremist Organizations are not curbed and controlled immediately, they would take the opportunity of:-

- (i) mobilizing their cadres for escalating their secessionist, subversive, terrorist and violent activities;
- (ii) propagating anti-national activities in collusion with forces inimical to the sovereignty and integrity of India;
- (iii) indulging in increased killings of civilians and targeting of the police and security force personnel;
- (iv) procuring and inducting more illegal arms and ammunitions from across the international border;
- (v) extorting and collecting huge funds from the public for their unlawful activities.

3. It is further stated that these extremist organizations have openly declared the formation of an independent Manipur by secession of Manipur State from India as their objective and they have been employing and engaging in armed means to achieve the aforesaid objectives, they have been attacking the security forces, the police, the government employees and law abiding citizens in Manipur. They have been indulging in acts of intimidation, extortion and looting of civilians for collection of funds for their organizations, they have been making efforts to establish contacts with sources abroad for influencing

public opinion and for securing their assistance by way of arms and training for the purpose of achieving their secessionist objective and they have been maintaining camps in neighboring countries for the purpose of sanctuary, training and clandestine procurements of arms ammunitions. It is further submitted that the activities of the Meitei Extremist organisations are detrimental to the sovereignty and integrity of India. For the aforesaid reasons and grounds, the Central Government came to the conclusion that the said organizations were unlawful associations.

4. The Government of India while declaring the Meitei Extremist Organisations as "Unlawful Associations" under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, for a further period of two years w.e.f. 13.11.2009, also considered the following points:

- i) Continued espousal of the policy of secession of Manipur from India;
- ii) Continued engagement in activities prejudicial to the sovereignty and integrity of India;
- iii) Continued adoption of violence and terror through armed action as a means of achieving their objective;
- iv) High level of extortion and illegal collection from the public including businessmen, traders and even Government employees;
- v) Links and support to other North-East insurgent groups and with neighbouring countries;

- vi) Procurement of large quantities of sophisticated arms and ammunition through clandestine channels or by snatching from police and security forces.

5. The Central Government declared the Meitei Extremist Organizations as Unlawful Associations vide its notification No. 2883 (E) dated 13th November, 2009. The Central Government in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, constituted this Tribunal vide Gazette Notification No. S.O. 3180 (E) dated 11th December 2009, for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the said Meitei Extremist Organisations to be Unlawful Associations as required by Sub-section (1) of Section 4 of the Act.

6. On the aforesaid reference having been made, this Tribunal vide order dated 23rd December, 2009 in pursuance of the provision of Section 4(2) of the Act, issued notice to the aforesaid Meitei Extremist organisations to show cause within 30 days from the date of the service of the said notices as to why the said Organizations should not be declared unlawful. This Tribunal also directed that the notices be served in the following manner:

- (i) By affixing a copy of the notice at some conspicuous part of the office(s), if any, of the Associations;

- (ii) By publication in a national newspaper in English and in one vernacular newspaper of the State of Manipur in which the activities of the aforesaid organizations are ordinarily carried on, and which are under circulation in the State of Manipur.
- (iii) By serving a copy of the notice, wherever possible, on the principal office bearers, if any, of the Associations;
- (iv) By pasting the notice on the Notice Board of the office of the District Magistrate or the Tehsildar at the Headquarters of the District or the Tehsil, as the case may be, in which the principal office(s) of the Associations are situated; and
- (v) By proclaiming by beat of drums or by means of loudspeakers, the contents of the notice in the area in which the activities of the Associations are ordinarily carried on; and
- (vi) By making an announcement over the radio from the local or nearest broadcasting station of the All India Radio;

7. The Tribunal also directed its Registrar to supervise the service of notices. The report of the Registrar as regards service of notices was also filed. The affidavit of service was filed by the Union of India.

8. From the material placed on record as well as report of the Registrar of the Tribunal, the Tribunal was satisfied that the notices had been duly served on the aforesaid organizations/associations as

per the directions of the Tribunal as prescribed under Rule 6 of the Unlawful Activities (Prevention) Rules, 1968.

9. In spite of opportunities having been afforded by Tribunal's orders dated 23.12.2009, 10.2.2010, 23.2.2010, 4.3.2010, 22.3.2010, 1.4.2010, and 8.4.2010 to the Meitei Extremist Organizations to file their replies/affidavits and have themselves represented before the Tribunal on the dates of hearing, none of the organizations has made any appearance, nor has any cause been shown in response to the notice.

10. In the hearing of the Tribunal held at Shillong on 22.3.2010 part evidence of **PW-1, Mr. Devesh Deval, Joint Secretary (Home), Government of Manipur** was recorded and his deposition was deferred to the next date of hearing to enable him to produce some more documents. The following officers of the Government of Manipur, who had filed their affidavits by way of evidence were examined on oath and their depositions were recorded:

PW-2 Mr. Sarangthem Ibomcha Singh, Dy.SP(CDO), Imphal;

PW-3 Mr. Md. Hushne Jaman, SDPO, Moirang, Manipur;

PW-4 Mr. K. Meghachandra Singh, SDPO, Lamlai, Imphal East District, Manipur;

PW-5 Mr. T. Lalboi Haokip, SDPO, Thoubai, Manipur;

11. In the hearing of the Tribunal held at Delhi on 1.4.2010 the evidence of the following officer of the Government of India, who had filed his affidavit by way of evidence was examined on oath and his deposition was recorded:-

PW-6, Mr. R. R. Jha, Director (North East), Ministry of Home Affairs, Government of India.

On the same date, the remaining evidence of PW-1, Mr. Devesh Deval, Joint Secretary(Home), Government of Manipur was recorded.

12. In the hearing of the Tribunal held at Guwahati on 8.4.2010 the following officers of the Government of Manipur, who had filed their affidavits by way of evidence were examined on oath and their depositions were recorded:-

PW-7 Mr. Th. Vikramjit Singh, SDPO, Singjamei, Manipur;

PW-8 Mr. Laishram Birbabu Singh, SDPO, Porompat, Imphal (East) Manipur;

PW-9 Mr. N. Madhunimai Singh, SDPO, Imphal (West), Manipur;

PW-10 Mr. M. Rameswar Singh, SDPO, Moreh, Manipur.

13. During their examination-in-chief, all the aforesaid witnesses admitted their signatures on their respective affidavits and tendered their affidavits along with all the exhibits mentioned therein and enclosed therewith as a part of their evidence.

14. None appeared before the Tribunal for the aforesaid Meitei Organizations for the cross examination of the witnesses in spite of affording opportunities as aforesaid. The witnesses were therefore discharged. Since no representation, communication or any document

had been received from the aforesaid extremist organizations, either by this Tribunal or its Registrar, the evidence was thus concluded.

15. Arguments were addressed by Mr. A.S. Chandhiok, ASG, assisted by Mr. Baldev Malik, Advocate on behalf of the Union of India. Learned counsels request that the Notification No.2883(E) dated 13.11.2009 issued under Section 3 (1) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 by the Central Government, whereby the aforesaid Meitei Extremist Organizations had been declared as unlawful organizations, be confirmed.

16. The Tribunal has perused the documentary evidence placed on the record as also the affidavits and the oral evidence adduced by the Union of India and the State of Manipur.

17. PW-1 Mr. Devesh Deval, Joint Secretary (Home), Government of Manipur in his affidavit by way of evidence has stated that the problem of insurgency has been plaguing Manipur for the past several years and the same is the creation of Meitei Extremist Organizations, namely, the Peoples' Liberation Army (PLA), an armed wing of the organization known as the Revolutionary Peoples' Front (RPF); the Peoples' Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK); the United National Liberation Front (UNLF); the Kanglei Yaol Kanba Lup (KYKL); the Kangleipak Communist Party (KCP); and the Manipur Peoples' Liberation Front (MPLF). It was stated by him that the State Government of Manipur has to deal with the problem of insurgency in the State of Manipur created by these Meitei Extremist Organizations and that the main objective of these organizations, as claimed by

them, is to secede Manipur from the Union of India and for the formation of an independent sovereign country. In other words, the liberation of the State of Manipur from the dominion of India was stated to be the objective of the said organizations. It was further stated by the said witness that in order to achieve this objective, the said Meitei Extremist Organizations have been indulging in various unlawful activities, such as intimidation, extortion of money from the general public, terrorization of the people by their acts of killing of innocent people, Government employees, police personnel and the security force personnel, kidnapping and abduction of top ranking Government officials, businessmen and the members of the well-to-do families for ransom by demanding huge amount etc. It was also stated that in the pursuit of fulfilling their objective, these organizations have been receiving assistance from foreign countries, particularly the neighbouring countries, by way of shelter and sanctuary, training, procuring of arms and ammunitions.

18. As regards the Revolutionary Peoples' Front (RPF) and the Peoples' Liberation Army (PLA), it has been stated that these organizations have training centres in Myanmar and Bangladesh. It is also stated that RPF is the political wing and that PLA is the armed wing. Both these wings are part of the same organization. It has been stated that their modus operandi is to move in two wheelers or hijack four wheelers with small arms or automatic weapons in the town areas and in the outskirts. It is also stated that they even move openly in groups wearing combat dresses with full gear and arms and

they attack police stations/ outposts and lay ambush against security forces and collect funds from Government Departments, employees, businessmen etc. They are said to have close nexus with other similar organizations, such as NSCN(K), UNLF, PREPAK, TPDF, ULFA, KCP, UPPK etc. It is also a member of the Manipur Peoples' Liberation Front (MPLF) which was formed on 01.03.1999 by a joint declaration signed by the Chairmen/Presidents of the PREPAK, RPF and UNLF. It has further been stated by PW-1 that these two wings have more than 550 sophisticated weapons like AK-47, AK-56, AK-86, M-16, M-18, M-21, M-22, M/20, M-23, LMG and Rocket Launchers etc. in addition to about 2000 other arms.

19. Similar statements have been made by the PW-1 with regard to United National Liberation Front (UNLF), Peoples' Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK), Kanglei Yaol Kanba Lup (KYKL), Kangleipak Communist Party (KCP), and Manipur Peoples' Liberation Front (MPLF).

20. Alongwith the affidavit of PW-1, attested copies of FIRs registered against the Meitei Extremist Organizations for the period 13.11.2007 to 15.06.2009 along with seizure memos have been filed and the same have been marked as Exhibits PW1/4 to 1/9. Ex PW1/10 (Colly) consists of the synopsis of the crimes committed by the various banned organizations, seized documents like literature, leaflets etc, newspaper clippings and details of justification for immediate declaration of these groups as unlawful associations. Ex. PW1/11 is the list of abbreviations referring to police stations as used in the reports. The attested copies of the special reports prepared by

the Superintendent of Police on the activities of these organizations are collectively marked as Ex.PW1/12. Ex.PW1/13 are the copies of the press releases issued from time to time by these organizations in local newspapers.

21. It has been deposed by PW-1 that these banned organizations routinely boycott national functions, namely, Independence Day and Republic Day every year. They issue press releases urging people not to participate in these functions and because of the fear created by these organizations, public attendance is very thin in such functions. In view of the aforesaid facts, the State Government has recommended for continuation of the declaration of these aforementioned organizations as unlawful associations. The deponent has further submitted that inspite of the sincere efforts being made by the Government of Manipur and the Government of India, they have not been successful in achieving their goal and that of late, the activities of these organizations have increased a lot and, therefore, the need to declare these organizations as unlawful exists even today so as to enable the Government of Manipur to deal with the law and order problems effectively.

22. Statements of 8 officers of Manipur Police Service were recorded. These witnesses, namely, PWs 2 to 5 and PWs 7 to 10 tendered their respective affidavits in evidence, and deposed about the investigations done by them in respect of different FIRs. These witnesses stated that the ban imposed on the aforesaid organizations ought to be continued.

23. PW-6, Mr. R.R.Jha Director, Ministry of Home Affairs, Government of India, tendered his affidavit dated 9.2.2010 in evidence and stated that in Manipur militant activities are mainly carried out by the Meitei outfits. In view of the prevailing security situation in Manipur, the entire State of Manipur excluding Imphal municipal area had been declared as disturbed area under the Armed Forces(Special Power) Act, 1958 by Governor of Manipur from time to time. He further stated that declared objective of the aforesaid organizations is to establish a sovereign State of Manipur by secession of Manipur State from India and these outfits have been engaging in armed means to achieve their objectives.

24. He further stated that the fragile law and order situation in the State of Manipur remains a cause of concern. The Security Forces remain the prime target of Meitei outfits. The details of violent incidents by these militant organizations as given in para 4 of his affidavit are reproduced below:-

Year	Total Incidents	Incidents by Meitei UGs	Total Civilians/SFs Killed by Meitei UGs	SFs killed by Meitei UGs
2007	584	396	122	37
2008	740	492	94	10
2009 (till December 31st)	659	485	77	17

25. He further deposed that these outfits have also been boycotting the celebration of National Festivals. Apart from violent activities they

indulge in extortions from general public and siphoning of development funds by coercion. The Meitei outfits have intensified their campaign against non-Manipuri residents of the State. Meitei outfits were involved in killing of 22 non-Manipuris in the State as compared to 21 killings of non-Manipuris in the whole year of 2008. These outfits have been extending support to parochial Meitei organizations for organizing agitation on various issues including the protection of the territorial integrity of Manipur and withdrawal of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 with a view to perpetuate the rift and animosity among different communities in the State. The gist of incidents committed by these organizations relating to the period between 2.1.2009 to 29.5.2009 are marked as Ex.PW6/P2.

26. He deposed that the Meitei UG outfits maintain close links with other extremist organizations in the North East such as United Liberation Front of Asom (ULFA), All Tripura Tiger Force (ATTF) and National Liberation Front of Tripura (NLFT) which have been declared unlawful associations under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967. They have also been maintaining links with National Socialist Council of Nagaland [NSCN (I/M)] and National Socialist Council of Nagaland [NSCN (K)]. The Meitei UG outfits have been maintaining links with other extremist organizations with a view to secure their assistance for procurement of arms and also for training of their cadres for the purpose of achieving their secessionist objectives. He further deposed that the PLA/RPF, UNLF, PREPAK, KCP, KYKL and MPLF have camps in Bangladesh and Myanmar and maintain training centres

in these countries. They have also been procuring arms and ammunition from these countries for carrying out their anti India activities in Manipur:

27. PW-6 further deposed that these organizations have been declared unlawful associations with effect from the date of notification as it had been felt by Central Government that there should not be any gap between expiry of date of previous notification and the present notification so that the police and security forces continue to apprehend and take effective actions against these organizations and they do not engage themselves in anti-national activities. The said Notification dated 13.11.2009 issued by the Government of India is marked as Ex.PW6/P3.

28. The Tribunal has also examined the secret documents which had been handed over by the State of Manipur and the Central Government in separate sealed covers.

29. The Tribunal has gone through the documentary evidence placed on record and the affidavits and oral evidence adduced by the Union of India and the Government of Manipur.

30. The evidence led on behalf of the Central Government and the Government of Manipur has not been controverted. There is nothing on record to contradict the same. There appears no reason to disbelieve the statements made by the various witnesses and the documentary evidence which has been filed in support of the oral testimonies and the affidavits by way of evidence.

31. After considering the entire evidence and all the material placed on the record, the Tribunal is of the view that there was sufficient cause for declaring the Meitei Extremist Organizations to be unlawful. Consequently, the Tribunal confirms the declaration made by the Central Government in the Notification No.2883(E) dated 13.11.2009 issued under Section 3 (1) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967.

[F. No. 11011/34/2009-NE-III]

NAVEEN VERMA, Jt. Secy.

04.05.2010